भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4155

19.08.2025 को उत्तर के लिए नियत

इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन

4155. **श्री ईश्वरस्वामी के.:**

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री का लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष लगभग 400 गीगावाट घंटों (जीडब्ल्यूएच) की बैटरी क्षमता की आवश्यकता होगी;

(ग) यदि हां, तो सरकार की इस संभावित मांग को किस प्रकार पूरा करने की योजना है;

(घ) क्या सरकार ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि लिथियम बैटरी के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला एक महत्वपूर्ण खनिज है और इसकी वैश्विक मांग बढ़ रही है, घरेलू स्तर पर बैटरी अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश करने की योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) से (ग): सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की वार्षिक बिक्री का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है। बैटरियों की आवश्यकता मांग पर आधारित है तथा बैटरी क्षमता की आवश्यकता के लिए ऐसा कोई आकलन नहीं किया गया है।

(घ) और (ङ): जी हां, उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम के तहत, अनुसंधान एवं विकास में निवेश कार्यक्रम समझौते का हिस्सा है। पीएलआई एसीसी स्कीम लाभार्थी फर्मों को पात्र निवेश मानकर प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए प्रोत्साहित करती है और यह स्कीम नियत तिथि से पांच वर्षों के भीतर कम से कम 60% मूल्य संवर्धन प्राप्त करने पर जोर देती है, जिससे प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) तथा स्थानीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है। इस फोकस से घरेलू सेल घटक विनिर्माताओं को स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला में एकीकृत करने, प्रौद्योगिकीय उन्नतियों को हासिल करने और आयात निर्भरता को कम करने से लाभ मिलने की उम्मीद है।

******